चुनावी बॉन्ड

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था, शासन और आईआर) से संबंधित है।

द हिन्दू

06 अप्रैल, 2022

चुनाव बॉन्ड योजना के खिलाफ जल्द ही मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने मंगलवार को अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा कि अदालत सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ लंबे समय से लंबित चुनौती को लेना चाहती थी, लेकिन COVID-19 महामारी ने मामले को खराब कर दिया।

याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री भूषण ने सीजेआई को सूचित किया कि मामला सुनवाई के बिना एक साल से लंबित था।

असीमित दान

चुनावी बॉन्ड योजना और 2017 के वित्त अधिनियम में संशोधन वित्त पोषण के स्रोतों के किसी भी रिकॉर्ड के बिना व्यक्तियों और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों को असीमित दान की अनुमति देता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश और वकील के बीच आदान-प्रदान तब हुआ जब बाद वाले ने सुनवाई के लिए मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का मौखिक उल्लेख किया। "आइए देखते हैं, हम इस मामले को उठाएंगे," मुख्य न्यायाधीश ने कहा। इसी तरह श्री भूषण ने पिछले अक्टूबर में तत्काल सुनवाई की माँग की थी।

फंड में पारदर्शिता

हालाँकि, सरकार ने इस योजना को उचित ठहराते हुए कहा कि इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इसने राजनीतिक फंडिंग में काले धन को खत्म करने के उपाय के रूप में इस योजना का बचाव किया था।

"वे [बॉन्ड] एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के साथ अपने बैंक खातों के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है। बॉन्ड में दाता या प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल का नाम नहीं होता है और केवल एक अंतर्निहित सुरक्षा सुविधा के रूप में एक अद्वितीय छिपा हुआ अल्फान्यूमेरिक सीरियल नंबर होता है," यह सरकार के 21-पृष्ठ के हलफनामे में कहा गया था।

सरकार ने इस योजना को "कैशलेस-डिजिटल अर्थव्यवस्था" की ओर बढ़ रहे देश में "चुनावी सुधार" के रूप में वर्णित किया था।

गुमनामी वैध

हालाँकि, भारत के चुनाव आयोग ने 2019 में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक फंडिंग के लिए सरकार की योजना ने गुमनामी को वैध कर दिया है।

चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दाताओं और योगदान प्राप्त करने वाले दलों की पहचान की रक्षा करते हैं।

चुनावी बॉन्ड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान देने वाले दाताओं को अपनी पहचान विवरण, जैसे स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. चुनावी बॉन्ड अधिसूचित बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं।
2. राजनीतिक दल को चुनावी बॉन्ड को उस खाते में भुनाना होगा जो भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(क) केवल 1

(ख) केवल 2

(ग) 1 और 2 दोनों

(घ) कोई नहीं

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements.

1. Electoral bonds are issued by notified banks.
2. Political party has to encash electoral bonds into the account which is registered with the Election Commission of India.

Which of the above statements is /are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) None

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. चुनावी बॉन्ड योजना की विभिन्न विशेषताओं और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। (250 शब्द)

Q. Discuss the various features of and issues related with electoral bond scheme. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।